

SHRI ANAND SHARMA: You ask the hon. Finance Minister to come prepared. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Vivek Gupta. ...*(Interruptions)*... You can ask this to the Finance Minister, not this Minister. ...*(Interruptions)*... She replied whatever she can. ...*(Interruptions)*... She replied to the extent possible. ...*(Interruptions)*... Shri Vivek Gupta. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर: सर, वित्त मंत्री जी मना कर चुके हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Neeraj Shekharji, sit down. ...*(Interruptions)*... Shri Vivek Gupta. You start speaking. Mr. Neeraj Shekhar, it is not going on record. ...*(Interruptions)*...

श्री नीरज शेखर: *

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing else will go on record. ...*(Interruptions)*... Mr. Neeraj Shekhar, sit down. ...*(Interruptions)*... You speak. It is going on record.

Need for ban on electronic gadgets inside aircraft cabin in flights from some countries

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, recently, the US and the UK airports banned all electronic items larger than mobile phones, like tablets, laptops and DVD players from being taken into the cabin of airplane.

Through you, Sir, I would request that our country also review this arrangement, because we are also on the high terrorist threat. But the larger issue here is, everyday different guidelines are being issued by different airlines. Some airlines say, 'You can take tablets inside.' Some airlines say, 'You have to check your tablet.' So, there are no uniform guidelines being issued by the Ministry of Civil Aviation and the airlines are creating so much of confusion at airports. When you go to security check counter, you will be sent back and we have to go back and check our luggage. So, there is utter chaos at airports.

Sir, through you, I wish to request the Government and the hon. Minister of Civil Aviation to look into this problem.

The bigger problem is: There are vacancies of about 2,500 CISF staff, according to various airports, making our airports more vulnerable. Sir, 26 hyper sensitive airports are still not covered by the CISF and we don't know who are handling security there. Various travel advisories are issued by other countries, but we seem to be lagging behind it. Whenever a ban is imposed, I would like the Government

* Not recorded.

to issue a centralized ban, so that there is no confusion to passengers and they can easily go to airports. Thank you.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I associate myself with the Zero Hour submission made by my colleague.

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, I also associated myself with the Zero Hour submission of Shri Vivek Gupta.

SHRI AHAMED HASSAN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the Zero Hour submission.

श्री रणविजय सिंह जूदेव (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

Need to include Awadhi language in the Eighth Schedule to the Constitution

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश): सर, मैं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी के लोगों की जन-भावनाओं को प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 3 करोड़ से अधिक उत्तर भारतीयों की मूल भाषा अवधी है। ये उत्तर प्रदेश में, बिहार के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में और झारखंड में बोली जाती है। मान्यवर, मुंबई में भी बड़ी संख्या में अवधी-भाषी रहते हैं। इस भाषा में कई बड़ी-बड़ी कालजयी रचनाएं हुई हैं, जोकि अनादिकाल से चली आ रही हैं और चलती रहेंगी, जिस में तुलसी दास जी की रामचरित मानस, हनुमान चालीसा शामिल हैं। मान्यवर रसखान जैसे महान कवि ने भी अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। इसी भाषा के आधार पर एक अवध प्रांत की स्थापना भी हुई थी, जिसका भू-भाग उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इसमें बहुत साहित्य उपलब्ध है, भाषा भी सशक्त है, उसका व्याकरण भी है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी हम देख रहे हैं कि इस भाषा को कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। इसलिए धीरे-धीरे इस भाषा को वांछित आधार नहीं मिल सका। मान्यवर, एक बड़े भू-भाग के करोड़ों लोगों की यह मांग है कि इस भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं सूची में दर्ज किया जाए और इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

मान्यवर, जहां तक अवधी का सवाल है, हमारे सामने बैठे लोग अवधी के नायकों का उपयोग तो करते हैं और वे उनका उपयोग जरूर करेंगे, लेकिन ये कभी भी अवधी भाषा का promotion नहीं करते। मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): अवधी में बोलिए।

श्री प्रमोद तिवारी: अवधी बहुत अच्छी भाषा है। हम यही चाही थी कि अवधी भाषा भारत के संविधान के अठवीं सूची में दर्ज हो जाए। हम यही बात कहन खातिर यहां पर खड़ा भई और हम कह सकी थी कि आप हिन्दी समझ पाएं या न समझ पाएं या कोई और भाषा समझ पाएं या न समझ पाएं, डिप्टी चेयरमैन सर, आप अवधी भाषा जरूर समझ जाएंगे। ...**(व्यवधान)**... हम यही तो बोलत हैं और का बोलत हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अवधी भाषा भारत की आठवीं सूची में दर्ज होय। यही खातिर हम यहां पे फरियाद करे खातिर खड़ा भई। हम चाहें कि अवधी भाषा का भारत के संविधान के आठवीं सूची में दर्ज होइ जाइ।